

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 11, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 02, 2021 <i>Kartika 11, Tuesday, Saka 1943- November 02, 2021</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2021

जी.एस.आर. 237 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/ एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 01-01-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 01, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 13 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 13 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-नियम (3), (4), (5) और स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

“(3) सामान्यतः 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी बोलियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (अ.प्र.बो.) की प्रक्रिया अनुज्ञात नहीं की जायेगी। यदि 200 करोड़ रुपये से नीचे की सरकारी बोलियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत की जाती है तो वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा। यदि उपापन की विषयवस्तु ऐसी है कि कारण लेखबद्ध किये जाने के पश्चात्, उपापन करने वाली

संस्था की राय में अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली को अंगीकृत किया जाना लोकहित में होगा तो, 200 करोड़ रुपये से ऊपर की सरकारी बोलियों में अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली अंगीकृत की जा सकेगी।

(4) राज्य में किसी लोक उपापन में भागीदारी के लिए भारत की सीमाओं से लगे हुए देशों से संबंधित या हिताधिकारी स्वामित्व वाले बोलीदाता, राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग में पूर्व रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ही अनुज्ञात किये जायेंगे।

(5) उपर्युक्त उप-नियम (2) और, यथास्थिति, (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, धारा 6 की उप-धारा (4) के खण्ड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट भारत की आवश्यक सुरक्षा और युद्धनीतिक हित को संरक्षित करने के लिए भारत की रक्षा, या राष्ट्रीय सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए उससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित मामलों के आधार पर, किसी देश या देशों या देशों के वर्ग के बोलीदाताओं से उपापन पर, पूर्व रजिस्ट्रीकरण और/या छानबीन को सम्मिलित करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी, ऐसे निर्बंधनों के उल्लंघन में कोई उपापन नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (i) “अभिकर्त्ता” से अन्य के लिए कोई कृत्य करने या तृतीय व्यक्ति के साथ व्यवहार में अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ii) “हिताधिकारी स्वामी” से अभिप्रेत है,-
 - (क) किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के मामले में, “हिताधिकारी स्वामी” वह प्रकृत व्यक्ति है या वे प्रकृत व्यक्ति हैं, जो चाहे अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से कृत्य कर रहा है या कर रहे हैं, जिसके/जिनके पास, नियंत्रक स्वामित्व हित है या जो अन्य व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रण करता है/करते हैं;
 - (ख) “नियंत्रक स्वामित्व हित” कंपनी के अंशों या पूंजी या फायदों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या उसकी हकदारी है;
 - (ग) “नियंत्रण” में निदेशकों की बहुसंख्या को नियुक्त करने या प्रबंध या नीतिगत निर्णयों, जिनके अंतर्गत उनकी अंशधारिता या प्रबंध अधिकारों या अंशधारकों के करारों या मतदान करारों के आधार पर किये गये नीतिगत निर्णय आते हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित होगा;
 - (घ) भागीदारी फर्म के मामले में, “हिताधिकारी स्वामी” वह प्रकृत व्यक्ति है या वे प्रकृत व्यक्ति हैं, जिसके/जिनके पास, चाहे वह अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से कृत्य कर रहा है या कर रहे हैं, भागीदारी की पूंजी या उसके फायदों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी या स्वामित्व है;
 - (ङ) अनिगमित संगम या व्यष्टि निकाय के मामले में “हिताधिकारी स्वामी” वह प्रकृतव्यक्ति है या वे प्रकृत व्यक्ति हैं जिसके/जिनके पास, चाहे वह अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से कृत्य कर रहा है या कर रहे हैं, ऐसे संगम या व्यष्टि निकाय की संपत्ति या पूंजी या उसके फायदों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी या स्वामित्व है;

- (च) जहां उपर्युक्त उप-खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) या (ङ) के अधीन कोई प्रकृत व्यक्ति परिलक्षित नहीं किया गया है, “हिताधिकारी स्वामी” वह सुसंगत प्रकृत व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंधक पदधारी का पद धारण करता है;
- (छ) न्यास के मामले में, हिताधिकारी स्वामी या स्वामियों के परिलक्षण में न्यासकर्ता, न्यासी, न्यास में पन्द्रह प्रतिशत या अधिक का हित रखने वाले हिताधिकारी और नियंत्रण या स्वामित्व श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्रकृत व्यक्ति सम्मिलित होगा;
- (iii) “भारत की सीमाओं से लगे हुए देश के बोलीदाता” से अभिप्रेत है,-
- (क) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था;
- (ख) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था का कोई समनुषंगी;
- (ग) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत संस्था के माध्यम से सारतः नियंत्रित कोई संस्था;
- (घ) कोई संस्था जिसका हिताधिकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है;
- (ङ) ऐसी संस्था का कोई भारतीय (या अन्य) अभिकर्ता;
- (च) कोई प्रकृत व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है;
- (छ) कोई कन्सोरटियम या सहउद्यम जहां कन्सोरटियम या सहउद्यम का कोई सदस्य उपर्युक्त किसी के अधीन आता है।”

[सं. एफ. 2(1)/एफडी/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017]

राज्यपाल के आदेश से,
विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।